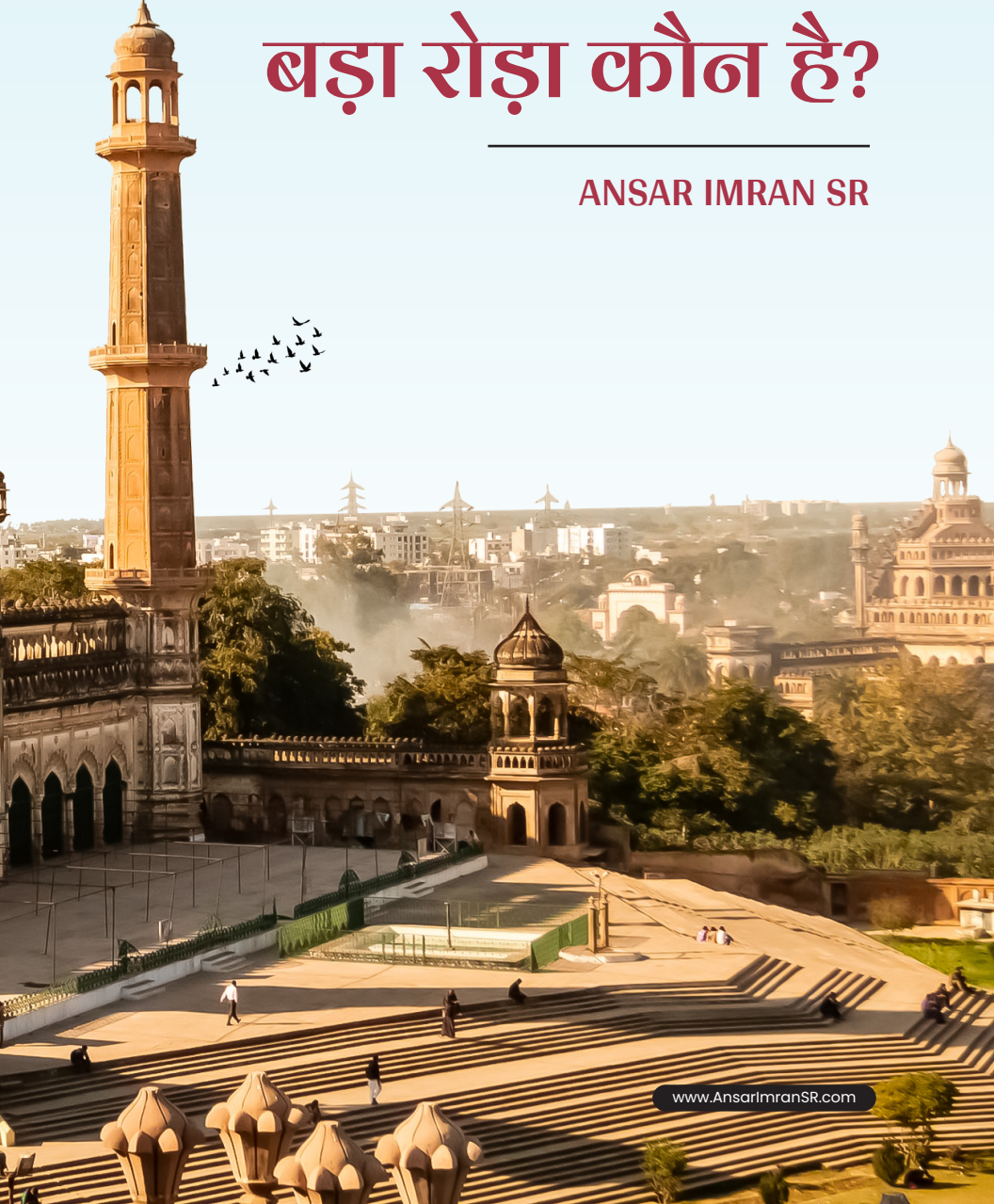


मुसलमानों की आजाद राजनीतिक आवाज में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है?

ANSAR IMRAN SR



मुसलमानों की आजाद राजनीतिक आवाज में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है?

ठेकेदार मौलाना या कथित सेकुलर पार्टियां?

इस सवाल का जवाब जितना दिखने में आसान लगता है उतना असल में है नहीं। एक लंबा इतिहास है जिसमें इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश हमारे पुरखों द्वारा की गई है।

चलिए इस उभरते हुए सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करते हैं!

सबसे पहली बात कि इस वक्त मुसलमान राजनीतिक तौर पर दो रास्तों पर खड़ा है। मगर इससे भी आगे बढ़कर एक रास्ता तो मुसलमानों को बेहद क्लियर है कि वो भाजपा को किसी कीमत पर राजनीतिक तौर पर वोट देने को तैयार नहीं है।



मुस्लिम राजनीति पर दो विचार:

पहला विचार:

एक तरफ मुसलमान समाज की एक बड़ी गिनती जिसमें युवा अधिकतर शामिल है वह इस बात के लिए मुखर हो रहे हैं और उनके दिल और दिमाग में बार-बार यह बात आ रही है कि मुसलमानों के साथ भारत में राजनीतिक तौर पर मक्कारी की जा रही है।

वो समझते हैं कि इस मक्कारी का इलाज उनको ढूँढना पड़ेगा तभी उनकी तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। उनकी नजर में मुसलमानों की जो सरकारी सतह पर प्रताड़ना हो रही है उसको उनकी आज़ाद मुस्लिम राजनीतिक आवाज कम करने का काम करेगी।

उन को एक बात की बेहद स्पष्टता हो चुकी है कि जिनको वह अपना राजनीतिक मसीहा समझते थे उन्होंने उनको हर पहलू से, हर डगर पर केवल ठगने का ही काम किया है।

जिन राजनीतिक पार्टियों को, जो अपने आप को कथित तौर पर सेकुलर कहती थी उन्होंने उन पार्टियों को एक तरफा तौर पर अपना समर्थन दिया, इस उम्मीद के साथ कि वह उनको सामाजिक सुरक्षा और उनके पिछड़ेपन को दूर करने में सहायता करेगी मगर आखिर में वही मिला ढाक के तीन पात।

मुसलमानों ने अलग-अलग सेकुलर राजनीतिक पार्टियों को एक मुश्त वोट दिया इसके बावजूद इन राजनीतिक पार्टियों ने उनके साथ केवल मक्कारी के सिवा कुछ नहीं किया है।

ये पार्टियां हमेशा नए नवेले बहानों के साथ एक ही राग अलापती रहती हैं कि देश में सम्प्रदायक ताकतें सर उठा लेंगी, वो सत्ता के शिखर पर बैठ जायेंगी मगर इसके बावजूद ये तल्लव हकीकत है कि वो कम्युनल पार्टी देश की सत्ता पर तीसरी बार काबिज हो चुकी है और ये पार्टियां केवल डफली बजा रही हैं।



ममता बनर्जी



अखिलेश यादव



राहुल गांधी



तेजस्वी यादव

ये सेकुलर पार्टियां हमेशा भाजपा को हराने की ठेकेदारी मुसलमानों के कंधों पर डालते हुए उन्हें एक तरफा समर्थन देने को कहते रहे हैं और अभी तक जारी है।

इससे भी आगे बढ़कर जब मुसलमानों ने कहा कि मुसलमान समाज को उनकी आबादी के हिसाब से राजनीतिक तौर पर टिकट बंटवारे में हिस्सा दिया जाए तो यह पार्टियों अक्सर यह कह कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है कि अगर हम लोगों ने मुसलमानों को अधिक टिकट दिए तो हिंदू वोट का बंटवारा हो जाएगा, जिसकी वजह से सांप्रदायिक ताकतें जीत जाएंगे।

इसी चक्कर में अक्सर यह देखने को मिला है कि मुसलमानों को अक्सर मुस्लिम बहुल सीटों के अलावा कभी भी कहीं पर टिकट नहीं दिया जाता है। इससे भी आगे बढ़ कर जहाँ पर मुस्लिम बहुल भी हैं वहाँ पर भी भाजपा हराने के नाम पर डंडी मारने की कोशिश की जाती है। ऐसी सीटों के कई उदाहरण हैं जो हैं तो मुस्लिम बहुल मगर वहाँ से ये पार्टियां मुस्लिम समाज की जगह किसी दूसरे समाज के प्रत्याशी को चुनाव जितवाने का काम करते हैं।

टिकट बंटवारे का खेल और परिसीमन रूपी अन्याय

उदाहरण के साथ समझना हो तो जब 2019 में EVM की जगह लोगों के मुस्लिम विरोधी लहर में दिमाग हैक हुए थे और हिंदुत्वा का नशा उफान पर था तब मौजूदा विपक्षी नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे तो उनके लिए सेफ सीट के रूप में केरल की मुस्लिम बहुल वायनाड सीट को चुना गया था।

Loksabha AC	Muslim %	Winner	Year
Wayanad	41.30%	Priyanka Gandhi	2024
Wayanad	41.30%	Rahul Gandhi	2019
Wayanad	41.30%	M I Shanavas	2014

ऐसे ही परिसीमन के नाम पर नगीना, बहराइच, करीमगंज, राजमहल जैसी सीटों से मुसलमानों के राजनीतिक वजूद को खत्म कर दिया गया है।

Loksabha AC	Muslim %	Reserved for
Nagina	43.04%	SC
Bahraich	33.53%	SC
Karimganj	53.70%	SC
Rajmahal	33.30%	ST

ऐसे ही पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम बहुल सीट बहरामपुर में, जहां पर मुसलमान आबादी के लिहाज से बहुसंख्यक है इसके बावजूद एक लंबे अरसे तक वहां से सेकुलर पार्टी कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की चुनाव जीत कर सांसद बनते रहे है। ये सीट हमेशा मुसलमानों की राजनीतिक आवाज से महरूम रहा है मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उलटफेर करते हुए वहां से टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान चुनाव जीते हैं वो अलग बात है कि मुसलमान समाज के मुद्दों पर उनकी जुबान पर भी हमेशा ताला लगा रहता है।

Loksabha AC	Muslim %	Winner	Party	Year
Baharampur	52.00%	Yusuf Pathan	TMC	2024
Baharampur	52.00%	Adhir Ranjan Chowdhury	INC	2019, 2014, 2009, 2004, 1999

दूसरा विचार:

इसके बाद एक सबसे अहम कड़ी है जिसको मुसलमानों की तरफ से दूसरा रुख समझा जाता है। यूँ कह लें कि फिलहाल के समय में राजनीतिक तौर पर इस राय का वजूद और वजन थोड़ा ज्यादा है।

मुसलमानों की एक बड़ी गिनती जिसकी रहनुमाई दीनी क्रायद करते है और वो समाजिक तौर पर मुस्लिम समाज में अधिक प्रभाव रखते है उनका ये मानना है कि मुसलमानों की अपनी राजनीतिक आवाज जो मुस्लिम पार्टी की शकल में हो उसका वजूद नहीं होना चाहिए।

उनकी नजर में मुसलमानों को अब अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी चाहिए उनको इन्हीं सेकुलर पार्टियों का दागदार दामन पकड़ के आजीवन चलते रहना चाहिए।

यह सॉफ्ट संघी पार्टियां जो दें वह ले लो जो ना दें उसके लिए गिला शिकवा ना करो। इसमें अक्सर देखने को मिला है कि कुछ धार्मिक नेता खुद को स्वघोषित तौर पर कौम का ठेकेदार घोषित कर के समर्थन रूपी लिस्ट का सौदा अक्सर इन पार्टियों से करते रहते हैं।

यहां ये भी देखने को मिलता है कि अक्सर कुछ दीनी रहनुमा अपने उन धार्मिक संस्थानों की आड़ में, जिसमें आप दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करो अथवा देवबंद के साथ जमीयत की वो राजनीतिक तौर पर कुछ खास राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर लिस्ट जारी करने के समुदाय को फरमान जारी करने का भी काम करते हैं।

उदाहरण के साथ समझना हो तो दिल्ली जामा मस्जिद और बुखारी खानदान से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। मस्जिद के मिम्बर से कभी अब्दुल्ला बुखारी राजनीतिक फरमान जारी करते थे अब उनके बेटे अहमद बुखारी भी वही काम कर रहे हैं।



जब यूपी में 2012 का विधानसभा चुनाव था तो ये काम बहुत डंके के साथ हुआ था। जामा मस्जिद से सपा के समर्थन का ऐलान हुआ था और चुनाव बाद सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार भी बन गयी थी।



खास बात ये रही कि इसका भरपूर इनाम भी प्रदान किया गया था। उस समय के शाही इमाम अहमद बुखारी के दामाद उमर खान जो सहरानपुर से चुनाव हार गए थे उनको एमएलसी बना कर विधान परिषद भेजा था। ऐसे ही उनके एक रिश्तेदार वसीम अहमद खान को यूपी प्रदुषण कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष कैबिनेट रैंक के साथ बनाया गया था।



अपने शुरुआत से मुसलमानों की आज़ाद राजनीतिक आवाज की घोर विरोधी रही जमीयत उलेमा हिन्द भी इस कड़ी में दूसरा नाम है। यहां ज्ञात रहे कि मौजूदा समय में

जमीयत के सदर मौलाना महमूद मदनी 1998 में असम के धुबरी से लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ चुके हैं। फिर उन्होंने 2004 में रालोद के टिकट पर अमरोहा से चुनाव लड़ा था जिसमें वो दूसरे नंबर पर रहे थे। अपनी राजनीतिक निष्ठा की वजह से उनको 2006 में रालोद ने अपने कोटा से राज्यसभा भेज दिया था।



Election	AC	Muslim %	Candidate	Party	Votes
Lok Sabha 1998	Dhubri	72.30%	Mahmood Madni	SP	64,805
Lok Sabha 2004	Amroha	39.03%	Mahmood Madni	RLD	269,638
Rajya Sabha 2006	UP	NA	Mahmood Madni	RLD	2006-12

वहीं उनके पिता मौलाना असद मदनी भी कांग्रेस की तरफ से तीन बार (1968-74, 1980-86, 1988-94) राज्यसभा के सांसद रहे हैं।



Maulana Asad Madni

Member Parliament - RajyaSabha
Congress
1968-78, 1980-86, 1988-94

Election	AC	Candidate	Party	Year
Rajya Sabha	UP	Asad Madni	INC	1968-74
Rajya Sabha	UP	Asad Madni	INC	1980-86
Rajya Sabha	UP	Asad Madni	INC	1988-94

जमीयत और मौलाना बदरुद्दीन अजमल

जमीयत के मामले में सबसे रुचक पहलु ये है कि जब मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी AIUFD को बनाया तो कांग्रेस ने उस पार्टी को खत्म करने का हर तरीका इस्तेमाल किया था।

आईपीएस अब्दुर रहमान की किताब “Absent in Politics and Power” में तो यहां तक दावा किया गया है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को कांग्रेस ने अपने मदनी परिवार के प्रभाव से जमीयत के प्रदेश अध्यक्ष से हटवा दिया था। कांग्रेस इसके बाद भी मुस्लिम पार्टी AIUDF को खत्म करने अथवा कांग्रेस में विलय के तमाम षड्यंत्र करती रही मगर उसको अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुयी है।

“In the 1970s when Osmani, a prominent leader, formed the United Muslim Front in Assam, the Congress promised him the position of CM of Assam, and got him to merge his party with the Congress. After Osmani did so, he was made only a minister in Assam. Another example is from Assam itself. A few years ago when Ajmal formed the AIUDF, and it made some headway in the Assam elections, the Congress managed to remove him from the Assam unit of JUH to through the influence of the Madani family.”

Book: Political Exclusion of Indian Muslims (Page: 283)

सेकुलर पार्टियों की कूटनीति:

इसके बाद जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आती यही वो ये है कि इस मुस्लिम राजनीति की नूरा कुश्ती में हमेशा एक पक्ष विजेता होता है वो है सेकुलर राजनीतिक पार्टियां। इसकी सबसे बड़ी बाहुबली कांग्रेस पार्टी ही है। उसने कभी भी मुसलमानों आज़ाद राजनीतिक आवाज को उभरने ही नहीं दिया है। अगर कोई उभर भी गया हो तो उसको हमेशा तोड़फोड़ कर के अपने साथ विलय के लिए मजबूर कर दिया गया है।

कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम राजनीति को खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद हर हरबे का बखूबी इस्तेमाल किया है। अक्सर उन मुस्लिम पार्टियों के नेताओं ने कभी अपने निजी हितों तो कभी भरोसे के साथ कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया है मगर बदले में केवल धोखा ही मिला है।

कांग्रेस ने अपनी कूटनीति और कुछ धार्मिक नेताओं को अपने पाले में रख कर हमेशा मुसलमानों की मुखर आवाज को खत्म करने काम किया है। राष्ट्रीय सतह पर व्यापक असर वाली केवल तीन मुस्लिम पार्टियां AIMIM, IUML और AIUDF है। इनको खत्म करने के लिए सेकुलर राजनीति ने कितना जोर लगाया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है।

मौजूदा समय में AIMIM की ताकत:

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अगुआई वाली AIMIM का जनाधार आज के समय में तेलंगाना की सीमाओं से पार होते हुए महाराष्ट्र और बिहार में विधानसभा की ताकत तक पहुंच चुका है।



Name	Election	AC Name	State
Asaduddin Owaisi	Lok Sabha 2024	Hyderabad	Telangana
Majid Hussain	Assembly 2023	Nampally	Telangana

Name	Election	AC Name	State
Kausar Mohi-uddin	Assembly 2023	Karwan	Telangana
Mir Zulfeqar Ali	Assembly 2023	Charminar	Telangana
Akbaruddin Owaisi	Assembly 2023	Chandrayangutta	Telangana
Jaffer Hussain	Assembly 2023	Yakutpura	Telangana
Mohammed Mubeen	Assembly 2023	Bahadurpura	Telangana
Ahmed Bin Abdullah Balala	Assembly 2023	Malakpet	Telangana
Mufti Mohamad Ismail	Assembly 2024	Malegaon Central	Maharashtra
Akhtarul Iman	Assembly 2020	Amour	Bihar

मौजूदा समय में AIUDF की ताकत:

मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF आज के समय में असम की राजनीति में एक बड़ी ताकत है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में इस पार्टी को दरकिनार कर के कोई भी असम की राजनीति में प्रभावी नहीं हो सकता है।



Name	Election	AC Name	State
Abdul Aziz	Assembly 2021	Badarpur	Assam
Zakir Hussain Laskar	Assembly 2021	Hailakandi	Assam
Sujam Uddin Laskar	Assembly 2021	Katlicherra	Assam
Nizamuddin Choudhury	Assembly 2021	Algapur	Assam
Karim Uddin Barbhuiya	Assembly 2021	Sonai	Assam
Adv. Aminul Islam	Assembly 2021	Mankachar	Assam
Nazrul Hoque	Assembly 2021	Dhubri	Assam
Nijanur Rahman	Assembly 2021	Gauripur	Assam
Hafiz Bashir Ahmed	Assembly 2021	Bilasipara West	Assam
Samsul Huda	Assembly 2021	Bilasipara East	Assam

Name	Election	AC Name	State
Phanidhar Talukdar	Assembly 2021	Bhabanipur	Assam
Rafiqul Islam	Assembly 2021	Jania	Assam
Ashraful Hussain	Assembly 2021	Chenga	Assam
Mazibur Rahman	Assembly 2021	Dalgaon	Assam
Aminul Islam	Assembly 2021	Dhing	Assam
Sirajuddin Ajmal	Assembly 2021	Jamunamukh	Assam

मौजूदा समय में IUML की ताकत:

केरल और तमिलनाडु की राजनीति में इंडियन यूनिन मुस्लिम लीग की राजनीति प्रभाव व्यापक है। K. M. कादर मोहिदीन की अगुआई में इस समय IUML इन दोनों प्रदेशों की राजनीति में सेकुलर पार्टियों के गठबंधन में बड़ी ताकत मानी जाती है।



Name	Election	AC Name	State
A. K. M. Ashraf	Assembly 2021	Manjeshwar	Kerala
N. A. Nellikkunnu	Assembly 2021	Kasaragod	Kerala
M. K. Muneer	Assembly 2021	Koduvally	Kerala
T. V. Ibrahim	Assembly 2021	Kondotty	Kerala
P. K. Basheer	Assembly 2021	Eranad	Kerala
U. A. Latheef	Assembly 2021	Manjeri	Kerala
Najeeb Kanthapuram	Assembly 2021	Perinthalmanna	Kerala
Manjalankuzhi Ali	Assembly 2021	Mankada	Kerala
P. Ubaidulla	Assembly 2021	Malappuram	Kerala
P. K. Kunhalikutty	Assembly 2021	Vengara	Kerala
P. Abdul Hameed	Assembly 2021	Vallikkunnu	Kerala
K. P. A. Majeed	Assembly 2021	Tirurangadi	Kerala
Kurukkoli Moideen	Assembly 2021	Tirur	Kerala
K. K. Abid Hussain Thangal	Assembly 2021	Kottakkal	Kerala
N. Shamsudheen	Assembly 2021	Mannarkkad	Kerala

Name	Election	AC Name	State
E. T. Muhammed Ba-sheer	Lok Sabha 2024	Malappuram	Kerala
M. P. Abdussamad Samadani	Lok Sabha 2024	Ponnani	Kerala
P.V.Abdul Wahab	Rajya Sabha 2021	Kerala	Kerala
Haris Beeran	Rajya Sabha 2024	Kerala	Kerala

कांग्रेस और तमाम सेकुलर पार्टियों को लगता है कि मुसलमानों का वोट तो केवल उनके बाप की बपौती है इसलिए कोई भी मुस्लिम राजनीतिक वजूद उभरना नहीं चाहिए क्यूंकि वो उनसे उनका एक फिक्स वोट बैंक छीन लेगा।



डॉ. अयूब अंसारी



मौलाना तौकीर रज़ा



सिबगतुल्लाह अंसारी



मौलाना आमिर रशादी

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मजलिस का कांग्रेस ने ऐतिहासिक तौर पर क्या किया था ये किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। पीस पार्टी, इत्तेहाद कौंसिल और कौमी एकता दल के साथ सेकुलर राजनीति ने क्या किया है ये भी आपके लिए एक मिसाल होनी चाहिए। एक समय में उलेमा कॉउंसिल बटला हाउस प्रकरण के बाद उभर कर सामने आयी थी मगर उसकी आज के समय में क्या हैसियत रह गयी है अब खुद अपनी आँखों से उसे स्पष्ट देख सकते हैं।

बिहार की राष्ट्रीय मजलिस पार्टी, महाराष्ट्र की अवामी विकास पार्टी, पश्चिम बंगाल की इंडियन सेकुलर फ्रंट और तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का क्या वजूद है आप खुद पता कर सकते हैं। 2009 में यूपी में लोकतांत्रिक पार्टी का सपा में विलय में बहुत कुछ बताता है।



अब्वास सिद्दीकी

आज के समय में AIMIM का देशव्यापी उभार अक्सर इन राजनीतिक पार्टियों को तकलीफ देता है। यही वजह है कि जिस बिहार में मजलिस की तरफ से 5 विधायक

जीत कर आये थे उनमें से 4 विधायकों को राजद ने तोड़ कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। महाराष्ट्र में भी इम्तियाज़ जलील की अगुआई में मजलिस का प्रदर्शन MVA को बहुत तकलीफ की अनुभूति प्रदान करता है।

मौजूदा समय में मुस्लिम युवाओं में AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी का बढ़ता क्रेज इन सेकुलर पार्टियों को मजलिस पर हमलावर होने के लिए मजबूर कर देता है। उनकी नजर में जिस मुस्लिम राजनीति को वो हमेशा सेटल कर लेते थे वो अब उनके कंट्रोल से जरा बाहर होती जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि देश का 15% फिक्स मुस्लिम वोट उनके हाथ से निकल अपनी राजनीतिक आवाज की तरफ अग्रसर हो जाए।



दीनी रहनुमाओं का रोल:

आज के समय में एक बात और अच्छे से जान लीजिए। जब कभी भी मुस्लिम राजनीति के किसी भी पहलु में आप आगे बढ़ेंगे तो मुसलमानों के कुछ दीनी रहनुमा जो खुद को राजनीतिक नुमाइंदा भी घोषित करते हैं वो सेकुलरिज्म और लोकतंत्र को बचाने के नाम पर मुसलमानों को कुछ कथित सेकुलर पार्टियों को वोट करने के लिए आह्वान करते हुए नज़र आयेंगे।

हाल ही में हुआ महाराष्ट्र चुनाव इसकी सबसे बेहतरीन उदहारण है। चुनाव से एक महीने पहले तक सब कुछ सेट था, लोगों का पूरा रुझान तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा गठबंधन को सत्ता से हटाने का माहौल बना हुआ था। मुस्लिम राजनीति के तहत भी लोगों ने AIMIM को अधिकतर जगह पर समर्थन का मन बनाया हुआ था।

मगर फिर इसमें एंट्री होती है मौलाना सज्जाद नौमानी की। वो एक समर्थन वाली लिस्ट ले कर प्रेस में पहुंच जाते हैं और एक एक सीट का नाम ले कर सेकुलर पार्टियों को समर्थन देने का ऐलान कर देते हैं। बीएस इस प्रेस कांफ्रेंस ने महाराष्ट्र के राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया और भाजपा के खेल में बम्पर तरीके से वापस आने की वजह भी बनी थी।



वैसे तो मौलाना नौमानी ने ऐलान किया था कि उनका ये समर्थन सम्प्रदायक राजनीति को हराने के लिए है मगर इसका उल्टा असर होता है। भाजपा के तब के सबसे बड़े चेहरा और अभी के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए अपने चुनावी मंचों से मौलाना के वीडियो दिखाते हुए इसे “वोट जिहाद” का नाम दे कर पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान में तब्दील कर देते हैं।



नतीजा ये निकला कि सेकुलर वोट तो एक मुश्त नहीं हुआ मगर भाजपा का कट्टर हिंदुत्व वाला कार्ड जैम कर चल गया। चुनाव परिणाम आने तो सभी हैरान क्यूंकि भाजपा गठबंधन चुनाव दो तिहाई के बहुमत से जीत चुका था और विपक्ष तो विपक्ष कहलाने लायक सीटें भी जीतने में नाकाम रहा है।

इस पुरे प्रकरण में मौलाना नौमानी के समर्थन में जिस बात से सबसे ज्यादा बवाल हुआ था वो ये था कि जो मौलाना कई सालों से मुसलमानों की आज़ाद राजनीतिक आवाज के पक्षधर थे वो अचानक से सेकुलरिज़्म के नाम उन पार्टियों को भी समर्थन देने का ऐलान करते हैं जो कल हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा थे।



प्रदेश में AIMIM के मुफ़्ती इस्माइल के अलावा बाकि सीटों पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को समर्थन ने मुस्लिम समाज में मौलाना के खिलाफ एक जबरदस्त रोष का माहौल बना दिया। अभी के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम राजनीति का सबसे मुखर चेहरा इम्तियाज़ जलील को भी समर्थन न देना मौलाना नौमानी के प्रति आम मुसलमानों के गुस्से की वजह बना था।



गजब तो ये हो गया कि जो शिवसेना कल तक हिंदुत्व की पोस्टर बाँथ थी और चुनाव में भी अधिकतर मुस्लिम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद उद्धव ठाकरे द्वारा केवल एक मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया था फिर भी मौलाना सज्जाद नौमानी ने शिवसेना को अधिकतर सीटों पर समर्थन का ऐलान किया था।

इसी प्रकार कुछ बवाल लोकसभा चुनाव 2024 में औरंगाबाद सीट को ले कर भी हुआ था। इस सीट पर तत्कालीन सांसद इम्तियाज़ जलील दुबारा चुनाव लड़ रहे थे। एक दम चुनाव के बीचों बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जमीयत के एक कथित जिम्मेदार इम्तियाज़ जलील के खिलाफ वोट करने का आह्वान करते हैं जिसके बाद वहाँ की राजनीति में खूब बवाल होता है। खूब सफाई पेश की जाती है मगर आम जनता में ये बात खूब अच्छे से फ़ैल जाती है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ने एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ ही झंडा उठा लिया है।



मुस्लिम राजनीती में सबसे अहम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र:

अगर आप मुस्लिम राजनीति को और ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको दो राज्यों की मुस्लिम राजनीति को जरा गहरायी से समझना होगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश मुस्लिम आबादी के हिसाब से दो बड़े राज्य माने जाते हैं जहाँ लोकसभा और विधानसभा के बड़ी गिनती में सीटें मौजूद हैं।

Winning MUSLIM CANDIDATES Maharashtra Assembly Election 2024



Aslam Shaikh
CONGRESS
Malad West
Margin - 6227



Mushrif Hasan
NCP
Kagal
Margin - 11581



Amin Patel
CONGRESS
Mumbadevi
Margin - 34884



Rais Shaikh
SP
Bhiwandi East
Margin - 52015



Sajid Khan Pathan
CONGRESS
Akola West
Margin - 1283



Abu Asim Azmi
SP
Mankhurd Shivaji Nagar
Margin - 12753



Sana Malik
NCP
Anushakti Nagar
Margin - 3378



Abdul Sattar
SS
Sillod
Margin - 2420



Mufti Mohd Ismail
AIMIM
Malegaon Central
Margin - 75



Haroon Khan
UBT
Versova
Margin - 1600

जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19.26% और महाराष्ट्र में 11.54% है। दोनों जगह पर अच्छी मुस्लिम आबादी के बावजूद आज तक मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुरूप राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है।

खास तौर पर महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। आबादी के अनुसार यहाँ पर कमसे कम 32-35 मुस्लिम विधायक होने चाहिए थे मगर हमेशा ये आंकड़ा 10 विधायकों तक ही सीमित रहता है। जो कि राजनीतिक हिस्सेदारी का एक तिहाई भी नहीं होता है। इस चुनाव में भी केवल 10 मुस्लिम विधायक ही चुने गए हैं।

Assembly	Winner	Party
Malad West	Aslam Shaikh	INC
Mumbadevi	Amin Patel	INC
Akola West	Sajid Khan Pathan	INC
Anushakti Nagar	Sana Malik	NCP
Kagal	Mushrif Hasan	NCP
Bhiwandi East	Rais Shaikh	SP
Mankhurd Shivaji Nagar	Abu Asim Azmi	SP
Sillod	Abdul Sattar	SS
Malegaon Central	Mufti Mohammad Ismail	AIMIM
Versova	Haroon Khan	UBT

इससे भी खतरनाक बात तो ये है कि प्रदेश की अधिकतर मुस्लिम बहुल सीटों पर सेकुलर पार्टियाँ मुसलमानों की जगह किसी दूसरे समुदाय को टिकट देती है। कुछ सीटों पर तो वो नेता कई सालों से चुनाव जीत कर विधायक सांसद बन रहे है।

मुम्ब्रा कलवा, भायखला, अमरावती, भिवंडी पश्चिम, धारावी, कुर्ला आदि ऐसी सीटें है जो वैसे तो मुस्लिम केंद्रित सीटें है मगर सेकुलर पार्टियाँ यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने से हमेशा कत्री कतराती है। परिसीमन के अन्याय ने इन सेकुलर पार्टियों को और बढ़ावा देने का काम किया है।

Assembly Constituency	Muslim %
Bhiwandi West	47.9
Amravati	46
Mumbra-Kalwa	43.5
Byculla	41.3
Akola West	41
Aurangabad Central	38.2
Aurangabad East	37.1
Dharavi (SC)	33.3
Versova	33.3
Vandre East	33
Kurla (SC)	30.7

सोच कर देखिये जिस प्रदेश में लगभग 12% मुस्लिम आबादी हो उस महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर किसी मुस्लिम को ये सेकुलर पार्टियां उम्मीदवार नहीं बनाती है। 2004 में कांग्रेस के कद्दावर नेता AR अंतुले के बाद कोई सांसद नहीं बना था। 2019 के चुनाव में केवल AIMIM से इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद का चुनाव जीत सांसद बने थे।



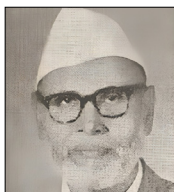
अभी तक महाराष्ट्र से चुने गए मुस्लिम सांसद:



**MUHAMMED
MOHIBBUL HAQ**
(Akola, 1962)



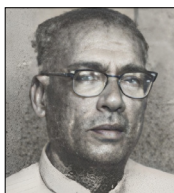
**GHULAM NABI
AZAD**
(Washim, 1980, 1984)



**SAMAD ALI
SAYYAD**
(Jalgaon, 1967)



QAZI SALEEM
(Aurangabad, 1980)



**KM ASGHAR
HUSSAIN**
(Akola, 1967, 1971)



HUSSAIN DALWAI
(Ratnagiri, 1984)



**ABDUL
SALEBHO**
(Mumbai, 1971)



**ABDUL REHMAN
ANTULAY**
(Raigad, 1989, 1991, 1996,
2004)



**ABDUL
SHAFEE**
(Chandrapur, 1971)



IMTIYAZ JALEEL
(Aurangabad, 2019)

इन सेकुलर पार्टियों द्वारा मुसलमानों को इस कदर नजरअंदाज किये जाने पर अब मुस्लिम समुदाय ने भयंकर तरीके से विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। जो पार्टियां कल तक राज्यसभा, विधान परिषद् आदि के लॉलीपॉप से मुस्लिम समाज को बहलाने की कोशिश करती थी उनसे बगावत करते हुए अब मुस्लिम समाज ने दूसरे विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश

अगर राजनीतिक हैसियत की बात करूं तो मेरी नजर में उत्तर प्रदेश के मुसलमान बाकि राज्यों के मुकाबले जरा बेहतर हैं।

यूपी में आबादी के हिसाब से मुसलमानों के लगभग 80 विधायक होने चाहिए थे मगर 2022 के चुनाव में केवल 34 मुस्लिम विधायक ही चुने गए थे। अलग अलग केस की वजह से 4 सीटों पर उप चुनाव हुए जिनमें से केवल दो पर ही मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत सके जिसकी वजह से ये गिनती फिलहाल 32 पर पहुंच गयी है। खास बात तो ये है कि इस चुनाव में 52 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव हारने की वजह से दूसरे नंबर पर रहे थे।

Sr	Name	Party	Assembly
1	Mehboob Ali	Amroha	Samajwadi Party
2	Naseer Ahmed Khan	Chamrauwa	Samajwadi Party
3	Nafees Ahmed	Gopalpur	Samajwadi Party
4	Bhawan Ashraf Ali Khan	Thana	Rashtriya Lok Dal
5	Mohd.Abdullah Azam Khan	Swar	Samajwadi Party
6	Haji Irfan Solanki	Sisamau	Samajwadi Party
7	Ziauddin Rizvi	Sikandarpur	Samajwadi Party
8	Iqbal Mahmud	Sambhal	Samajwadi Party
9	Mo.Azam Khan	Rampur	Samajwadi Party
10	Nadira Sultan	Patiali	Samajwadi Party
11	Alam Badi	Nizamabad	Samajwadi Party
12	Mo.Nasir	Moradabad Rural	Samajwadi Party
13	Suhaib alias Mannu Ansari	Mohammadabad	Samajwadi Party

Sr	Name	Party	Assembly
14	Abbas Ansari	Mau	SBSP
15	Maria Shah	Matera	Samajwadi Party
16	Zia ur Rahman	Kundarki	Samajwadi Party
17	Kamal Akhtar	Kanth	Samajwadi Party
18	Mohd. Hassan	Kanpur Cantt.	Samajwadi Party
19	Armaan Khan	Lucknow West	Samajwadi Party
20	Zahid	Bhadohi	Samajwadi Party
21	Mohammad Tahir Khan	Issauli	Samajwadi Party
22	Ataur Rahman	Baheri	Samajwadi Party
23	Shahid Manzoor	Kithor	Samajwadi Party
24	Rafiq Ansari	Meerut	Samajwadi Party
25	Tasleem Ahmed	Najibabad	Samajwadi Party
26	Farid Mahfouz Kidwai	Ramnagar	Samajwadi Party
27	Nawab Jan	Thakurdwara	Samajwadi Party
28	Sayyida Khatoon	Dumariaganj	Samajwadi Party
29	Ashu Malik	Saharanpur	Samajwadi Party
30	Ghulam Mohammad	Siwalkhas	Rashtriya Lok Dal
31	Mohd Faheem	Bilari	Samajwadi Party
32	Shahjil Islam Ansari	Bhojipura	Samajwadi Party
33	Umar Ali Khan	Behat	Samajwadi Party
34	Nahid Hassan	Kairana	Samajwadi Party

जब 2017 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड अपने उफान पर था उस समय मुस्लिम विधायकों की ये गिनती केवल 24 पर पहुंच गयी थी। अधिकतर मुस्लिम उम्मीदवार वोट बंटवारे की वजह से चुनाव हार गए थे। वैसे अमूमन राज्य की राजनीति में 40 से 50 मुस्लिम विधायक हमेशा रहे हैं।

मुस्लिम राजनीति अपनी चरमसीमा पर 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में पहुंची थी। इस साल 68 मुस्लिम विधायक चुन कर विधानसभा पहुंचे थे वहीं 63 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव हारने की वजह से दूसरे नंबर पर रहे थे।

अब अगर लोकसभा की बात करें तो प्रदेश की 80 सीटों में से आबादी के हिसाब से 16 सांसद होने चाहिए थे मगर 2024 के चुनाव में केवल 5 सांसद ही चुने गए हैं। राजनीतिक समीकरण के खेल की वजह से मुस्लिम ज्यादातर समय इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं। केवल 1980 के चुनाव में ही यूपी से 18 मुस्लिम सांसद चुने गए थे उसके बाद ये चमत्कार कभी नहीं हुआ है। इसके अलावा राज्यसभा में भी 1-2 मुस्लिम सांसद चुन कर पहुंचते रहे हैं।

Sr	Election Year	Member Parliament	Lok Sabha AC	Party
1	2024	Imran Masood	Saharanpur	Congress
2	2024	Iqra Choudhary	Kairana	Samajwadi Party
3	2024	Ziaur Rahman Barq	Sambhal	Samajwadi Party
4	2024	Afzal Ansari	Ghazipur	Samajwadi Party
5	2024	Mohibullah Nadvi	Rampur	Samajwadi Party

अब यहां पर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों का ठीक-ठाक अमल दखल है इसके बावजूद भी इस समय भाजपा सत्ता में बैठी हुई है। भाजपा की पूरी राजनीति ही मुस्लिम विरोध और चूड़ी टाइट करने पर टिकी हुयी है।



उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज भी अपनी खुद की राजनीतिक हैसियत को बनाने की जगह उनकी पारंपरिक सेकुलर पार्टियों के पीछे खड़ा है जो उनकी राजनीतिक हैसियत को खत्म करने की तरफ अग्रसर रहती है। समाजवादी पार्टी का मुसलमानों के साथ बोलचाल तरीके से खड़े रहने का ही नतीजा है कि 2022 विधानसभा और 2024 में मुसलमानों ने सपा को एक तरफ सपोर्ट किया है।

इसके अलावा कांग्रेस और बसपा भी मुसलमानों के लिए विकल्प के तौर पर रही है। इसी कड़ी में पश्चिमी यूपी में रालोद को भी मुसलमानों का समर्थन रहा है मगर भाजपा के साथ जाने के बाद मुसलमानों ने इनको भी दरकिनार करना शुरू दिया है।



जो पीस पार्टी 2012 में 4 विधायकों के साथ एक नयी ताकत बन कर उभरी थी वो इस समय अपने राजनीतिक वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल का भी सपा में विलय हो चुका है। उलेमा कौंसिल कभी बड़ी ताकत बनने की तरफ अग्रसर थी मगर उनका भी राजनीतिक वजूद खत्म की तरफ है।

रही बात इस समय मुस्लिम पॉलिटिक्स की पोस्टर बॉय AIMIM की तो उसका प्रदेश की राजनीती में कभी भी वो वजूद नहीं बन पाया है जैसा जनता का समर्थन उसको



तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार में देखने को मिला है। अब इस बनवास की वजह हो सकती है जिसमें सबसे बड़ी वजह तो प्रदेश में मुसलमानों के मुद्दों पर गायब रहना प्रमुख कारण हो सकता है।



अब इस पूरी किस्सा कहानी का निष्कर्ष क्या है?

आखिर किसको मुस्लिम राजनीति के वजूद में सबसे बड़ा रोड़ा समझा जाये?

मुझे लगता है इस मामले में कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है। हर पहलु से इस मामले में अड़ंगा डाला गया है। केवल कुछ दीनी रहनुमाओं को जिम्मेदार ठहरा देना भी ज्यादाती होगी। एक सोच है जो अभी भी मुस्लिम समाज के अधिकतर समूह में व्यापक है कि मुसलमानों की अपनी आज़ाद राजनीतिक आवाज नहीं होनी चाहिए। जिसका बड़े पैमाने पर फायदा सेकुलर पार्टियां खास तौर पर कांग्रेस उठाती है।

अगर कोई कोशिश मुस्लिम राजनीतिक पार्टी बनती भी है तो दो कारणों से हमेशा उसका वजूद अधर में लटक जाता है। अक्सर नेताओं के निजी हित इस मामले में आड़े आ जाते हैं। वो अपने निजी राजनीतिक फायदों के लिए विलय की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे ही स्थापित सेकुलर पार्टियां भी अपनी कूटनीति से उभरती मुस्लिम पार्टी को खत्म करने पर उतारू रहती हैं।



अब दूसरी बात ये है कि मुसलमानों की तरफ से अभी भी कुछ इलाकों को छोड़ मुस्लिम राजनीति को अमूमी तौर पर कबूल नहीं किया गया है। मुस्लिम राजनीती का सबसे बड़ा रोड़ा तो यही है। जिस दिन लोगों को ये समझ में आ जायेगा कि दूसरी सेकुलर पार्टियों में रहने और अपनी आज़ाद आवाज होने से उनको क्या फायदा है वो खुद ब खुद इसके लिए अपने कदम बढ़ाने शुरू कर देंगे।



एक उदाहरण से समझिए। मुस्लिम राजनीति का गढ़ केरल में IUML का दबाव ही है कि वहां के मुसलमानों को शिक्षा में 8% और सरकारी जॉब में 10% आरक्षण का प्रावधान है।

ऐसे ही AIMIM के गढ़ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए OBC कोटा के तहत 4% आरक्षण का प्रावधान है।

असल बात ये है कि मुस्लिम समाज खास तौर पर उत्तर भारत में जिस दिन दबाव की राजनीति को करना सीख गया उसी दिन मुस्लिम राजनीति के मामले में एक क्रांति का उदय होगा।

बाकि आपकी नजर में मुस्लिम राजनीति के वजूद में कौन बड़ी रुकावट है!



Ansar Imran SR

मैं हमेशा से ही भारत की राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लिखना बेहद पसंद करता हूँ। मैंने अभी तक अधिकतर समय में भारत की राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारी, विभिन्न समुदायों के मानवधिकार उल्लंघन, मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम आदि जैसे अहम मुद्दों पर ही समाजिक चेतना के लिए काम किया है। इस पुस्तक में मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी पर सेकुलर पार्टियों के कुठाराघात और मुसलमानों की अपनी राजनीतिक आवाज़ में जो रुकावट हैं उन पर खुल कर अपने विचार प्रगट किया हैं। उम्मीद है कि आप सभी को इस पुस्तक से भारतीय राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी के मुद्दे को समझने में सहायता मिलेगी।

